जुड़िए हमसे... पर @risingindore.news 0731-4032200

राइजिंग इन्दौर

सच का सारथी

इंदौर, बुधवार, 21 मई 2025

वर्ष -12, अंक-21

मूल्य 2 रूपए, पेज- 8

Inside
page 08

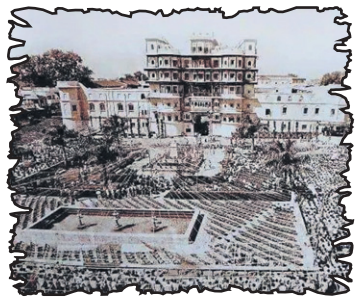

एम वाय अस्पताल के पीछे बनेगा नया एम वाय

मंत्री परिषद की बैठक में इंदौर को 2 सौगात

इंदौर महानगर क्षेत्र के विकास और नियोजन का अधिनियम मंजूर

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

प्रदेश मंत्रिमंडल की इंदौर के राजवाड़ा में आयोजित बैठक में इंदौर को दो सौगात देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट के द्वारा इंदौर महानगर क्षेत्र के विकास और नियोजन का अधिनियम मंजूर किया गया। इसके साथ ही अस्पताल के पीछे की खाली पड़ी जमीन पर नया एम वाय अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए यह दोनों फैसले इंदौर के दूरगामी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है।

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के 300 वें जयंती वर्ष पर उनके आदर्शों और मूल्यों को समर्पित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक इंदौर में राजवाड़ा के दरबार हॉल में हुई। मंत्रि-परिषद ने 3 हजार 867 करोड़ रुपये की योजना और निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यकम योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। इसमें युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। योजना में जरूरतमंद व्यक्ति बैंक ब्याज में एक हजार रुपए प्रतिवर्ष छूट के साथ पूरे जीवनकाल के लिए अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति व्यक्ति ऋण के ब्याज पर छूट प्राप्त कर सकेगा। प्रतिवर्ष योजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम-2025 को स्वीकृत

करने का निर्णय लिया हैं। अधिनियम- 2025 लागू होने के बाद महानगर योजना समिति एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश में इंदौर-उज्जैन-देवास-धार एवं भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़) के लिए महानगर योजना समिति एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय संविधान में विहित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का क्षेत्रीय स्तर पर समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए महानगर योजना समिति एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए घोषणा की गई थी। महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार कर महानगर योजना समिति से विकास योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की विकास योजना को अनुमोदन प्रदान करने के बाद विकास योजना का क्रियान्वयन महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। महानगर क्षेत्र की विकास योजना में ऐसे क्षेत्र की भौगोलिक आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विकास हो सकेगा, जिससे कि रोजगार एवं आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

शेष पेज 2 पर

राइजिंग इंदौर अब risingindore.com और MAGZTER.com पर डिजिटल रूप में भी उपलब्ध...

पेज 1 से जारी...

महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय परिसर इंदौर और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के उन्नयन के लिए 1095 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इस स्वीकृति के अनुसार महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर से संबद्ध महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय परिसर में 773 करोड़ 7 लाख रुपए से प्रस्तावित नवीन चिकित्सालय भवन, मिनी ऑडिटोरीयम, नर्सिंग हॉस्टल, पार्किंग एवं बाह्य विकास कार्य आदि का निर्माण किया जाएगा। रीवा में श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में ओ.पी.डी. ब्लॉक, मेटरनिटी ब्लॉक, स्टॉफ क्वार्टर, नर्सिंग कॉलेज तथा हॉस्टल एवं अन्य कार्य के लिए 321.94 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष-2028-29 तक निरंतरता की स्वीकृति दी। इसमें आगामी 4 वित्तीय वर्षों 2025-26, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए राज्यांश राशि 167 करोड़ 74 लाख रुपए और निकाय अंशदान राशि 59 करोड़ 31 लाख रुपए, कुल राशि 227 करोड़ 5 लाख रुपए का व्यय अनुमानित है। योजना में राशि का प्रयोग प्रदेश के नगरीय निकायों में सेप्टिक टैंक से निकलने वाले स्लज के परिवहन के लिए डी-स्लजिंग वाहन, सीवर लाईन की सफाई के लिए सफाई उपकरणों, ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन के लिए वाहन तथा नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई मित्रों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एवं पीपीई किट के लिए अनुदान प्रदान कर तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाएगा। राज्य स्तर पर संचालित नगरीय स्वच्छता की समस्त गतिविधियों को समेकित कर मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम का आरम्भ 28 अगस्त 2012 को किया गया था।

4 औद्योगिक क्षेत्र में 249 करोड़ की लागत से वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को बढ़ाने, बेहतर वातावरण प्रदान करने और महिलाओं के कामकाजी जीवन को आसान बनाने के लिए प्रदेश के 4 औद्योगिक क्षेत्र में 249 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति दी है। विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन, पीथमपुर सेक्टर-1 एवं 2 जिला धार, मालनपुर घिरौंगी (भिंड) एवं मंडीदीप (रायसेन) में कामकाजी महिला छात्रावासों अंतर्गत कुल 26 हॉस्टलों और भवनों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक में 222 बेड की क्षमता होगी। इस प्रकार कुल 5 हजार 572 बेड क्षमता के होस्टलों का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अन्तर्गत एमपीआईडीसी लि. द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट 2024-25 स्कीम में वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण किया जाना है। वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स में आधुनिक सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, फूड कोर्ट और मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध होगा। कामकाजी महिला छात्रावासों में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और नौकरी के अवसरों की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाएगी। रियायती दरों पर भोजन एवं न्यूनतम किराए पर बेड उपलब्ध कराया जाएगा। बुनियादी अधोसंरचनाओं जैसे-पार्किंग, रिक्रिएशनल रूम, पेन्ट्री, डायनिंग एरिया, कॉमन टॉयलेटस, कॉमर्शियल दुकानें इत्यादि सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। कार्यरत महिलाओं के बच्चों की उचित देखभाल के लिए झूला घर का भी प्रावधान किया गया है।

प्रदेश की जीएसडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य

वर्ष 2047 के विकसित मध्य प्रदेश पर किया गया मंथन

वर्ष 2047 के विकसित मध्यप्रदेश के लिए इंदौर में आयोजित की गई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंथन किया गया। इस बैठक में प्रस्तुत किए गए दृष्टि पत्र में कहा गया है कि हमें प्रदेश की जीएसडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर की बनाना है।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष पर राजवाड़ा इंदौर में विकसित मध्यप्रदेश @2047 दृष्टिपत्र पर मंत्रि-परिषद ने मंथन किया। लोकमाता देवी अहिल्याबाई के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप विकसित मध्यप्रदेश बनाने के लक्ष्यों और प्रक्रिया पर सदस्यों की विस्तृत चर्चा हुई। वर्ष 2047 तक प्रदेश का समेकित विकास करते हुए सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 15.03 लाख करोड़ से बढ़ाकर 250 लाख करोड़ (2 ट्रिलियन डॉलर) करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को एक लाख 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 22 लाख रुपए करने का भी लक्ष्य रखा गया है।

अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि दृष्टि पत्र में वर्ष 2047 में एक समृद्ध मध्यप्रदेश की परिकल्पना की गई है जो कि सभी के सामूहिक प्रयासों से संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्यप्रदेश की नींव पर निर्मित होगा। इस प्रकार वर्ष 2047 का मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणा मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के अनुसरण से निर्मित होगा। मध्यप्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने एवं प्रदेश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से हितधारक परामर्श एवं जन सहयोग से विकसित मध्यप्रदेश @2047 दृष्टि पत्र को तैयार किया गया है। दृष्टि पत्र को धरातल पर वास्तविक रूप से साकार करने के लिए रोडमैप का मंत्रि-परिषद के सदस्यों के समक्ष सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया।

दृष्टि पत्र में वर्ष 2047 में अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में विस्तृत रूप से मंत्रि-परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया। 8 थीमैटिक ग्रुप्स में उद्योग, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र तथा वनोत्पाद, सेवाएं और अधोसंरचना एवं नगरीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन एवं नागरिक सेवाओं का प्रदाय और वित्तीय नियोजन एवं संवर्धन पर प्रेजेंटेशन दिया गया। मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मंत्रि-परिषद के सदस्यों को बताया गया कि मध्यप्रदेश @2047 दृष्टिपत्र के क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा। राज्य के सभी विभागों की योजनाओं, लक्ष्यों एवं कार्य बिंदुओं की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। साथ ही लाइव डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा।

मध्यप्रदेश @2047 दृष्टि पत्र के निर्माण का कालक्रम

देश के 75 वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में, प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का प्रयास किए जाने का आह्वान किया गया था। इसे साकार करने के लिए विकसित मध्यप्रदेश @2047% दृष्टि पत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मध्यप्रदेश के योगदान को सुनिश्चित करने, मध्यप्रदेश संकल्प पत्र-2023% के लक्ष्यों की पूर्ति करने एवं राज्य के समग्र विकास को दिशा देने के लिए विकसित मध्यप्रदेश @2047 दृष्टिपत्र तैयार किया गया। विकसित मध्यप्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में अप्रैल 2024 में नीति आयोग, भारत सरकार से प्रारंभिक चर्चा की गई। माह मई से सितम्बर 2024 के मध्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव स्तर के 8 थीमेटिक समूहों में व्यापक परिचर्चा के बाद विकसित भारत @2047 के लिए मध्यप्रदेश के सुझाव और अभिमत नीति आयोग को प्रेषित किए गए। नवंबर 2024 में सीईओ नीति आयोग एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में लिए गए निर्णय अनुसार और नीति आयोग के मार्गदर्शन में राज्य स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसमें जनप्रतिनिधियों के सुझाव, विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा, जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता, नागरिक सर्वेक्षण, उद्योग संगठनों के साथ चर्चा, शिक्षाविदों के साथ चर्चा और फील्ड विजिट शामिल रही। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई, जिसके मार्गदर्शन में 8 थीमैटिक ग्रुप्स का गठन किया गया। 8 थीमैटिक गुप्स में उद्योग, कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र तथा वनोत्पाद, सेवाएं, अधोसंरचना एवं नगरीय विकास, शिक्षा, स्वास्थय, सुशासन एवं नागरिक सेवाएं प्रदाय और वित्तीय नियोजन एवं संवर्धन को शामिल किया गया। प्रत्येक ग्रुप द्वारा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता और अन्य हितधारकों के सुझावों का समावेशन सुनिश्चित करते हुए दृष्टि पत्र तैयार किया गया है।

शत-प्रतिशत साक्षरता, नवकरणीय ऊर्जा को 75 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश @2047 दृष्टिपत्र अनुसार वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि 43 प्रतिशत, सेवाएं 36 और उद्योग 21 प्रतिशत योगदान देते हैं। वर्ष @2047 तक उद्योगों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देकर, रोजगार के अवसर सृजित कर अर्थव्यवस्था को संतुलित करते हुए जीडीपी में कृषि का योगदान 24-28 प्रतिशत, उद्योग का योगदान 21-25 प्रतिशत और सेवाओं का योगदान 49-53 प्रतिशत तक लाने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रति व्यक्ति औसत आयु को 67.4 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष @ 2047 तक 84 वर्ष से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साक्षरता दर को 75.2 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष @ 2047 तक 100 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में कुल ऊर्जा स्त्रोत में नवकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत 22.5 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत से अधिक किया जाएगा।

इंदौर नगर निगम में जुपिटर अस्पताल को 13 करोड़ संपत्तिकर वसूली राहत के लिए भोपाल तक ऐसे चली फाइल

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर नगर निगम ने जुपिटर हॉस्पिटल पर 13 करोड़ से अधिक का संपत्तिकर बकाया निकाला है, जिस पर प्रोजेक्ट कंपनी के एमडी डॉ. राजेश कासलीवाल ने आपत्ति जताई थी।

इंदौर नगर निगम में संपत्तिकर वसूली का मामला हो, जल कर का या फिर अन्य नियम का, आम व्यक्ति का मुद्दा आता है तो टूटकर कार्रवाई करता है। जैसे कि निगम की कुर्की कराने वाले मिश्रा के घर को सीज कर दिया गया। लाखों की टैक्स वसूली में निगम ढोल बजाकर मुनादी कराती है और संपत्ति पर नोटिस चस्पा करना, संपत्ति जब्त करना जैसी सख्ती होती है। लेकिन जहां हाईप्रोफाइल मामला आता है वहां नए रास्ते राहत देने के निकाले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है जुपिटर हॉस्पिटल का।

13 करोड़ की वसूली में राहत देने के लिए चली फाइल

जुपिटर हॉस्पिटल पर साल 2023 से ही नगर निगम ने 13 करोड़ 3 लाख 62 हजार रूपए का संपत्तिकर का बकाया निकाला हुआ है। इस पर जुपिटर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट प्रालि इंदौर के एमडी डॉ. राजेश कासलीवाल को आपत्ति है और उन्होंने इसके लिए अपील की। यह अपील खासी लंबी खींची गई। दिसंबर 2024 में कासलीवाल ने आवेदन लगाया कि उन्हें अस्पताल विस्तार के लिए दो मंजिला और बनाना है तो इसके लिए मंजूरी दी जाए। मंजूरी की फाइल भी चल गई। लेकिन मप्र शासन के भवन अनुज्ञा सॉफ्टवेयर एपीबीएएस टू में प्रावधान है कि यदि किसी पर संपत्तिकर बकाया है तो इसकी प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ेगी, यानी उनके पास संपत्तिकर बकाया नहीं ऐसा सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब यह हो नहीं सकता था ऐसे में निगम में एक नई अनूठी फाइल चली।

इस तरह फिर दौड़ी राहत की फाइल

डॉ. कासलीवाल ने निगम को आवेदन दिया और कहा कि वह उनकी अपील का निर्धारण होने पर, जो निगमायुक्त के पास लंबित है, टैक्स भर देंगे, लेकिन इसमें समय लग रहा है तो फिर उन्हें इस दौरान भवन अनुज्ञा की मंजूरी दी जाए। डॉ. कासलीवाल की बात मानते हुए नगर निगम ने भोपाल विभाग के लिए एक फाइल चलाई। अपर आयुक्त आईएएस रोहित सिसोनिया ने भोपाल को पत्र लिखा कि सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रावधान किया जाए कि बिना एनओसी की भवन अनुजा मंजूर हो जाए, इससे टैक्स डिमांड पर कोई असर नहीं होगा।

भोपाल के अधिकारी जागे और यह बोल दिया

इस फाइल के आते ही भोपाल में अधिकारियों के कान खड़े हो गए। अभी तक ऐसी कोई फाइल नहीं आई थी। उन्होंने तत्काल इससे इनकार करते हुए कहा कि इस तरह की राहत देने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है और बेहतर होगा कि निगम जुपिटर हॉस्पिटल की टैक्स अपील पर फैसला दे और टैक्स भरवाएं। इसके बाद अपने आप ही भवन अनुज्ञा हो जाएगी।

इसके बाद लंबी अपील पर फैसला हुआ, लेकिन मंजूरी नहीं

भोपाल से भी रास्ता बंद होने के बाद आखिरकार निगम ने कई महीनों से लंबित पड़ी डॉ. राजेश कासलीवाल की टैक्स अपील पर फैसला दिया और निगम की टैक्स बकाया राशि को सही बताते हुए टैक्स भरने का आदेश दिया। लेकिन जैसा कि टैक्स को लेकर पहले ही रास्ते निकाले जा रहे थे, इस मामले में डॉ. कासलीवाल ने निगम का फैसला आते ही इसके खिलाफ हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर कर दी। मामले में अभी सुनवाई जारी है।

जुपिटर हॉस्पिटल और निगम क्या बोल रहा है

इस मामले में जुपिटर हॉस्पिटल प्रबंधन ने मामला हाईकोर्ट में होने से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि जो भी होगा नियम से होगा, संपत्तिकर में कोई राहत नहीं दी गई है, जो भी हाईकोर्ट से फैसला होगा, पालन किया जाएगा।

जुपिटर हॉस्पिटल में यह बोर्ड में

जुपिटर हॉस्पिटल मूल रूप से मुंबई का ग्रुप है। डॉ. राजेश कासलीवाल ने इंदौर में पहले विशेष हॉस्पिटल बनाया था और फिर जुपिटर के साथ टाइअप हुआ। जुपिटर हॉस्पिटल में डॉ. राजेश कासलीवाल एमडी जुपिटर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स प्रालि इंदौर के पद पर हैं। वहीं वेबसाइट के अनुसार जुपिटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डॉ. अजय प्रताप ठक्कर चेयरमैन और एमडी हैं, वहीं सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में डॉ. अंकित अजय ठक्कर हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में वीएस राघवन के साथ ही डॉ. भास्कर पी. शाह, डॉ. दर्शन हीरालाल वोरा, डॉ. जास्मीन हीरालाल वोरा, डॉ. जास्मीन अमित पटेल, सतीश आर. उटेकर, उर्मी अश्विन पोपट व अन्य हैं।

सुपर कॉरिडोर की जमीन के लिए प्राधिकरण ने लिया बड़ा फैसला

9 लाख स्क्वायर फीट जमीन का होगा मल्टीपरपज उपयोग

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा सुपर कॉरिडोर की स्टेडियम के उपयोग के लिए आरक्षित की गई जमीन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत इस 9 लाख स्क्वायर फीट जमीन का मल्टीपरपज उपयोग किया जाएगा।

सुपर कॉरिडोर पर योजना 151 और 169बी में लगभग 9 लाख स्क्वेयर फीट जमीन प्राधिकरण के पास रीक्रिएशन उपयोग की मौजूद है, जो एमपीसीए ने भी क्रिकेट स्टेडियम के लिए सस्ते में मांगी थी। मगर अब इस जमीन को प्रदेश के सबसे बड़े मनोरंजन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्राधिकरण की आज होने वाली बोर्ड बैठक में इस जमीन पर मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाए जाने के लिए आर्किटेक्ट कंसल्टेंट की नियुक्ति के टेंडर जारी करने का निर्णय लिया जाएगा। यहां पर बड़े म्यूजिक शो, नाट्य मंचन के साथ एग्जीबिशन सहित अन्य गतिविधियां हो सकेंगी, जिसमें स्पोर्ट्स से जुड़े आयोजन भी शामिल रहेंगे। इंदौर में अभी दिलजीत, अरिजित सहित अन्य बड़े म्यूजिक शो निजी जमीन पर आयोजित होते हैं। अब प्राधिकरण इस तरह के कॉन्सर्ट के लिए एक आधुनिक सेंटर तैयार करेगा। देश में कॉन्सर्ट इकोनॉमी का एक नया और बड़ा सेक्टर है, जिससे राज्य सरकारें अच्छी कमाई कर सकती हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को इस कॉन्सर्ट इकोनॉमी को अपनाने की सलाह भी पिछले दिनों दी थी। उसी तारतम्य में है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जो कि नवाचार में पीछे नहीं रहते और अपने कार्यकाल में कई ऐसे नए सफल प्रयोग कर चुके हैं। उन्होंने भी इस तरह के प्रोजेक्ट को पसंद किया।

अभी 16 मई को इंदौर में रियल इस्टेट सेक्टर से जुड़ी रीजनल ग्रोथ समिट भी आयोजित की गई। उसके पूर्व आज प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कॉन्सर्ट सेंटर तैयार करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने भी अपनी समिट में भी इस तरह के सेंटर को उपयोगी बताया और प्राधिकरण के अफसरों को इस दिशा में भी काम करने को कहा। संभागायुक्त और प्राधिकरण अध्यक्ष दीपक सिंह का कहना है कि सुपर कॉरिडोर पर जो रीक्रिएशन उपयोग, जिसमें स्टेडियम भी आता है, उसके लिए भूखंड एसटीडी-वन मौजूद है। योजना 151 और 169-बी के सेक्टर-बी में 82588 वर्गमीटर यानी लगभग 9 लाख स्क्वेयर फीट जमीन का उपयोग अब मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाने में किया जाएगा और यह इंदौर शहर के साथ-साथ प्रदेश के लिए भी एक बड़ी सौगात रहेगी, जिसमें खेल गतिविधियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के म्यूजिक शो, नाट्यमंचन से लेकर एग्जीबिशन से लेकर अन्य तमाम आयोजन हो सकेंगे। इस तरह के कॉन्सटर्स और गतिविधियों के लिए जिस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसे प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाएगा। इसके लिए देश के ख्यातनाम ईवेंट और बड़े शो ऑर्गेनाइजरों से भी चर्चा की जाएगी। आज की बोर्ड बैठक में आर्किटेक्ट कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी करने पर निर्णय लेंगे। वहीं प्राधिकरण सीईओ आरपी अहिरवार के मुताबिक बोर्ड बैठक में आईएसबीटी के संचालन, स्टार्टअप पार्क, कन्वेंशन सेंटर के अलावा टीपीएस-8 और एमआर-11 के निर्माण में आ रही बस्तियों के व्यवस्थापन सहित सीनियर सिटीजन के लिए बनी बिल्डिंग के टेंडर मंजूरी सहित अन्य विषयों पर भी निर्णय होना है।

स्टेडियम की जमीन के लिए मिला था 200 करोड़ का सिंगल टेंडर

प्राधिकरण ने पिछले दिनों स्टेडियम की इस 20 एकड़ जमीन को टेंडर के जरिए बेचने के प्रयास किए और 200 करोड़ रुपए का सिंगल टेंडर प्राप्त हुआ और प्राधिकरण ने जो आरक्षित कीमत 23800 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की थी उसमें सिर्फ एक रुपए बढ़ाकर टेंडर जमा किया। मगर प्राधिकरण ने इस सिंगल टेंडर को मंजूर नहीं किया। शहर के दो बड़े कारोबारियों ने यह टेंडर जमा किया था।

क्रिकेट एसोसिएशन को चाहिए थी मुफ्त में यह जमीन

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी इस जमीन को पाना चाहते थे। संगठन इस जमीन पर स्टेडियम का निर्माण करना चाहता था इसके लिए वह रु. 1 प्रति स्क्वायर फीट के भाव से याने करीब करीब मुफ्त में ही यह जमीन पाना चाहता था। इसके लिए स्टेडियम के पदाधिकारी के द्वारा कई बार प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत भी की गई।

संपादकीय...

इंदौर में हर दिशा में चाहिए एक एमवाय

प्रदेश मंत्रिमंडल ने इंदौर में आयोजित बैठक में राज्य सरकार के द्वारा अस्पताल के पीछे की जमीन पर नया अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया। इस कार्य के लिए 750 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। सरकार का यह फैसला इंदौर की आवश्यकता की पूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण और आवश्यक फैसला है। इस फैसले से पूरे इंदौर संभाग के गरीब वर्ग के जो लोग इलाज के लिए इस अस्पताल में आते हैं उन्हें भविष्य में राहत देने और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा। इस समय जो स्थिति बन रही है यदि उसे देखा जाए तो इंदौर में चारों

■ गौरव गुप्ता

दिशाओं में एम वाय के जैसा बड़ा और अच्छे संसाधन वाला सरकारी अस्पताल चाहिए है। सरकार को अब इंदौर की चारों दिशाओं में इस तरह के उन्नत और सर्वश्रेष्ठ अस्पताल स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। सरकार के द्वारा इस दिशा में यदि पहल की जाती है तो वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में यदि कहा जाए तो समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की आंखों के आंसू पोंछने की दिशा में एक पहल मानी जाएगी। इस समय डबल इंजन सरकार होने के कारण यदि इस तरह की कोई पहल राज्य सरकार की ओर से होती है तो उसमें केंद्र सरकार से भी पर्याप्त आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है।

गर्मी में ठंडक, कैंसर से राहत, दिल का दोस्त, और कई फायदों की खान है मुलेठी एक जड़ी बूटी

गर्मी में ठंडक, कैंसर से राहत, दिल का दोस्त, जानें कितने फायदों की खान है ये एक जड़ी बूटी चिलचिलाती धूप, तपती धरती, बहता पसीना और गर्म हवाओं के थपेड़े में राहत देने वाली चीज है मुलेठी। डॉ.आरती मेहरा ने बताया कि गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए ठंडी तासीर वाली चीजें खाना जरूरी है। इसका बेहतरीन विकल्प है मुलेठी, ये न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी ठंडा-ठंडा कूल-कूल रखता है।

मुलेठी को अगर हम आयुर्वेद का खजाना कहे, तो शायद गलत नहीं होता। इसके सेवन से कई बीमारियों से या तो राहत मिलती है, या इनका खात्मा हो जाता है।

मुलेठी के फायदे

कैंसर में असरदार

छोटे-मोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को दूर करने में भी मुलेठी का यूज होता है। मुलेठी कैंसर के इलाज में कारगर है। इसमें मौजूद आइसोलिक्युरिटिजेनिन नामक तत्व पैंक्रियाटिक कैंसर समेत कई बीमारियों के लक्षणों को दबाने में कारगर होता है।

मुलेठी का काढ़ा पिएं

इंडियन किचन में पाए जाने वाली मुलेठी का आयुर्वेद में भी खासा स्थान है। डॉ. आरती मेहरा ने बताया कि कि जिन लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती या लू जल्दी लग जाती है, उन्हें इसका सेवन करना चाहिए। इससे शरीर को ठंडक मिलती है। यही नहीं, मुलेठी के पाउडर के साथ ही काढ़ा भी शरीर को ठंडक देने में मदद करता है। काढ़ा पीने से सेहत से जुड़ी कई परेशानियों में भी फायदा मिलता है।

डॉ. आरती मेहरा
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ
7999788456

डाइजेशन में मददगार

उन्होंने बताया, मुलेठी का काढ़ा शरीर और दिमाग के साथ ही पेट की गर्मी को भी शांत करता है। ठंडी तासीर के कारण ये डाइजेशन से जुड़ी परेशानियों से राहत देता है। नियमित रूप से इसके सेवन से गैस, अपच, खट्टी डकार, कब्ज जैसी समस्याएं भी खत्म होती हैं।

दिल की दोस्त

औषधीय गुणों से भरपूर मुलेठी हार्ट ब्लॉकेज रोकने में मददगार होती है। मुलेठी का सेवन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे दिल तक खून की सप्लाई बेहतर रहती है और हार्ट ब्लॉकेज की आशंका कम हो जाती है। मुलेठी में एंटीऑक्सिडेंट और प्रोटीन जैसे तत्व हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और सूजन भी कम होती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। मुलेठी का सेवन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है।

हार्ट पेशेंट कैसे करें सेवन?

हार्ट के मरीजों को 3 से 5 ग्राम मुलेठी के पाउडर को 15 से 20 ग्राम मिश्री वाले पानी के साथ रोजाना सेवन करने की सलाह दी जाती है, जिससे दिल की सेहत में सुधार होता है और हार्ट ब्लॉकेज का खतरा भी कम होता है. मुलेठी में एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हार्ट के सूजन और तनाव को कम करने में कारगर होते हैं, जो दिल की बीमारियों की रोकथाम में अहम भूमिका निभाते हैं.।

हिचकी से आराम दिलाती है

अगर आपको हिचकी आ रही है और बंद होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में मुलेठी को कुछ देर मुंह में रखकर चूसें। मुलेठी चूसने से थोड़ी ही देर में हिचकी आना बंद हो जाता है।

मुलेठी के फायदे सांसो से जुड़े रोगों में

मुलेठी का काढ़ा बनाकर 10-15 मिली मात्रा में पीन से सांस से जुड़े रोग ठीक होते है।

पेट के अल्सर में फायदेमंद

पेट का अल्सर एक गंभीर समस्या है और इसका इलाज कराना बहुत ज़रुरी है। मुलेठी को घरेलू उपायों के रुप में इस्तेमाल करके भी आप पेट के अल्सर को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच मुलेठी चूर्ण या मुलेठी पाउडर को एक कप दूध के साथ दिन में 3 बार सेवन करें। पेट में अल्सर होने पर मिर्च मसालों और तीखी चीजों से परहेज करें।

प्रेग्नेंट महिलाएं सतर्क रहें

हार्ट ब्लॉकेज के अलावा मुलेठी का सेवन मुंह के छाले, गला बैठने, गले की खराश और खांसी के लिए भी किया जाता है. पुरानी से पुरानी खांसी भी इसके रस के सेवन से खत्म हो जाती है. डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने ये भी बताया कि बिना डॉक्टर की सलाह के मुलेठी का सेवन नहीं करना चाहिए. गर्भवती महिलाओं को मुलेठी का सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए।

चेक अनादरण के प्रकरणों में कब तक नहीं हो सकती जेल - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के प्रकरणों के निराकरण के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि चेक बाउंस के मामले में आरोपी को पहली पेशी के समय तुरंत जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। आरोपी को अपना पक्ष रखने और मामले का सामना करने का उचित अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर आरोपी पर दोष साबित होता है, तो वह अपील का अधिकार रखता है और अपील के दौरान जमानत पर रह सकता है।

अंतरिम मुआवजे का प्रावधान

2019 में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसके तहत अंतरिम मुआवजे का प्रावधान जोड़ा गया। इसके अनुसार, चेक बाउंस का आरोपी अदालत में अपनी पहली पेशी के समय शिकायतकर्ता को चेक राशि का 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा दे सकता है। बाद में इस प्रावधान में बदलाव किया गया और पहली पेशी के बजाय अपील के समय अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। अगर बाद में आरोपी की अपील स्वीकार कर ली जाती है, तो उसे यह राशि वापस मिल जाती है।

चेक बाउंस के मामले में दोषी साबित होने पर भी आरोपी को अपील का अधिकार है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(3) के अनुसार, आरोपी सजा सुनाए जाने के 30 दिनों के भीतर सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके अलावा, धारा 389(3) के तहत वह अपनी सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा होने की अपील भी कर सकता है। इस तरह, आरोपी को अपना पक्ष रखने और न्याय पाने के कई अवसर मिलते हैं।

वर्तमान समय में चेक के माध्यम से भुगतान करना एक आम बात है। व्यापार हो या व्यक्तिगत लेनदेन, चेक एक सुरक्षित भुगतान विकल्प माना जाता है।

चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे आम है बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होना। जब आप किसी को चेक देते हैं, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके खाते में चेक पर लिखी राशि से अधिक या बराबर राशि मौजूद है। अन्य कारणों में चेक पर अस्पष्ट या गलत हस्ताक्षर, चेक की अवधि समाप्त होना, बैंक खाता बंद होना या फिर चेक में किसी प्रकार की कटिंग या ओवरराइटिंग होना शामिल है। इन सभी कारणों से चेक बाउंस हो सकता है

संजय मेहरा
हाईकोर्ट एडवोकेट
98270 74132

चेक बाउंस के मामले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। इस कानून की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले दर्ज होते हैं। इसके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है और वह चेक पर्याप्त धनराशि नहीं होने या अन्य कारणों से बाउंस हो जाता है, तो चेक जारी करने वाला व्यक्ति कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकता है। इस मामले में अधिकतम दो साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सजा का निर्धारण मामले की गंभीरता और अन्य परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। चेक बाउंस होने पर तुरंत जेल नहीं होती है, बल्कि इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सबसे पहले, जब किसी का चेक बाउंस होता है, तो चेक प्राप्तकर्ता (लेनदार) को चेक जारीकर्ता (देनदार) को एक कानूनी नोटिस भेजना होता है। यह नोटिस चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर भेजना आवश्यक है। इस नोटिस में देनदार को चेक की राशि 15 दिनों के भीतर चुकाने का निर्देश दिया जाता है। अगर 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तो लेनदार अगले 30 दिनों के भीतर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकता है।

कोर्ट में शिकायत दर्ज होने के बाद, अदालत आरोपी को समन जारी करती है। आरोपी को अदालत में पेश होना होता है और अपना पक्ष रखना होता है। इस दौरान आरोपी चेक की राशि जमा करके मामले को सुलझा सकता है। अगर आरोपी अदालत में पेश नहीं होता है या चेक की राशि नहीं चुकाता है, तो अदालत उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। मामले की सुनवाई के बाद, अगर आरोपी दोषी पाया जाता है, तो उसे सजा सुनाई जा सकती है।

चेक बाउंस के मामले में दोषी साबित होने पर भी आरोपी को अपील का अधिकार है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(3) के अनुसार, आरोपी सजा सुनाए जाने के 30 दिनों के भीतर सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके अलावा, धारा 389(3) के तहत वह अपनी सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा होने की अपील भी कर सकता है। इस तरह, आरोपी को अपना पक्ष रखने और न्याय पाने के कई अवसर मिलते हैं।

चेक बाउंस पर जेल कब होती है?

चेक बाउंस के मामले में जेल की सजा आम तौर पर तभी होती है जब सभी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद भी आरोपी राशि का भुगतान नहीं करता है और दोषी साबित होता है। चेक बाउंस के मामले में अधिकतम दो साल की जेल हो सकती है, लेकिन अधिकांश मामलों में छह महीने से एक साल तक की सजा सुनाई जाती है। हालांकि, अगर आरोपी चेक की राशि और अदालत द्वारा तय किए गए मुआवजे का भुगतान कर देता है, तो अक्सर सजा को कम किया जा सकता है या समझौता हो सकता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अनुसार, चेक बाउंस के मामले में पीड़ित को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। अदालत आरोपी को चेक की राशि से दोगुनी तक मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। यह मुआवजा पीड़ित को हुए नुकसान और परेशानी के लिए दिया जाता है। मुआवजे की राशि का निर्धारण मामले की परिस्थितियों, राशि की मात्रा और अन्य कारकों के आधार पर किया जाता है। चेक बाउंस से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सबसे पहले, चेक जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त राशि मौजूद है। चेक पर स्पष्ट हस्ताक्षर करें और कोई भी कटिंग या ओवरराइटिंग न करें। चेक की वैधता अवधि का ध्यान रखें और उसी के अनुसार चेक जारी करें। अगर आप किसी कारण से चेक की राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो तुरंत संबंधित व्यक्ति से बात करें और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था पर सहमति बनाएं। इन सावधानियों से आप चेक बाउंस से जुड़ी कानूनी समस्याओं से बच सकते हैं।

यूको बैंक के पूर्व CMD सुबोध कुमार गोयल गिरफ्तार 6200 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में ED की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूको बैंक के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुबोध कुमार गोयल को 16 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उन पर कोलकाता स्थित कंपनी कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (CSPL) से जुड़े 6,210 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं।

गोयल पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में CSPL को भारी मात्रा में ऋण मंजूर किए गए, जिन्हें बाद में फर्जी कंपनियों के माध्यम से गैरक़ानूनी रूप से स्थानांतरित किया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, गोयल ने इस मामले में नकद, संपत्तियां, और लग्जरी वस्तुएं अवैध रूप से प्राप्त कीं, जिन्हें कई शेल कंपनियों और परिवार के सदस्यों के जरिए छिपाया गया। गोयल को 17 मई को कोलकाता की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 21 मई तक ED की हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 1400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी बताई गई थी, लेकिन नवीनतम जांच में यह मामला 6,210 करोड़ रुपए तक का पाया गया है, जिसमें अन्य बैंकों से लिए गए ऋण भी शामिल हैं। यह मामला सीबीआई की प्राथमिकी से शुरू हुआ था, जिसमें CSPL को मिले क्रेडिट फैसिलिटी और उसके बाद ऋण के बड़े पैमाने पर ग़लत उपयोग को उजागर किया गया।

पेज 1 से जारी...

रंग पंजाब दे... पंजाबी सांस्कृतिक प्रोग्राम में चिंतन बाकीवाला और पंजाबी बच्चों की विशेष प्रस्तुति

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

रंग पंजाबी दे प्रोग्राम का आयोजन पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक इंद्रजीत सिंह खनूजा और संयोजक संजय मेहरा द्वारा किया गया। इस रूप में पंजाबी सांस्कृतिक प्रोग्राम के रूप में सजाने का काम मां अहिल्या सेवा संस्था की अध्यक्ष डॉ. आरती मेहरा और उपाध्यक्ष रश्मि बाकीवाला ने अपनी 10 दिन की मेहनत में एक सफल प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह रही कि इस प्रोग्राम में सभी लोग पंजाबी रंग में रंगी और पंजाबी संस्कृति से रूबरू हुए। चिंतन बाकीवाला C B रॉकस्टार और बॉलीवुड की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर और शानदार जानदार गायकी प्रस्तुत की गई। देश विदेश में पहचाने जाने वाले चिंतन बाकीवाला ने पंजाबी गानों की विशेष प्रस्तुति देकर पूरे हाल को झूमने नाचने भांगड़ा करने पर मजबूर कर दिया। उनकी विशेष प्रस्तुति और प्रसिद्धि के कारण मुख्य अतिथि बी के द्विवेदी और शंकर लालवानी और इंद्रजीत सिंह खनूजा द्वारा विशेष रूप से पंजाबी रतन के रूप में सम्मानित कर एक विशेष कृपाण भेंट की गई। पंजाबी सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी धर्म जाति और विधाओं के लोगों ने संस्कृति से रूबरू होकर एक खुशी जाहिर की। इसमें 5 प्यारे और 10 गुरु के बारे में भी जानकारी दी। जिन्होंने सिख और खालसा धर्म की स्थापना की। 5 साल से लेकर 20 साल के बच्चों और पंजाबी महिलाओं ने गिद्दा, जागो और भांगड़ा की प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। प्रोग्राम में हिट गानों की प्रस्तुति दी गई जिसमें इंदौर के प्रसिद्ध सिंगर अनु शर्मा, अल्तमस खान, मानसी पांडे, संध्या दवे आलोक वाजपेई गर्विता जैन, मोनिका व्यास, अजीत श्रीवास्तव, पिंटू सलूजा, दीपेश जैन द्वारा संगीत दिया गया।

स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम का इंतजार

पिछली बार के मुकाबले में सर्वेक्षण भी तीन महीने विलंब से हुआ

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इस बार इंदौर को प्रीमियर लीग में शामिल किया गया है। इसमें सूरत और नवी मुंबई भी है। तीनों शहरों में स्वच्छता के आंकलन का पैमाना अलग रहा। पिछले साल तीनो शहर टॉप थ्री में थे। हालांकि इस बार सर्वेक्षण के समय इंदौर की स्वच्छता की स्थिति बेहतर रही।

इंदौर नगर निगम को भरोसा है कि आठवीं बार सफाई में फिर वह फिर नंबर वन बनेगा, लेकिन अब तक परिणाम नहीं आए है। इंदौर सहित देश के चार हजार नगर निगमों में डेढ़ माह पहले ही स्वच्छता सर्वेक्षण हो चुका है। वर्ष

2024 स्वच्छता सर्वेक्षण घोषित ही नहीं हुआ,क्योकि सर्वेक्षण ही छह माह लेट हुआ था। इसका असर परिणामों की घोषणा पर भी नजर आ रहा है।

पिछले साल जनवरी में परिणाम घोषित हो चुके थे, लेकिन इस साल तो स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ही टीम मार्च माह में आई। इंदौर नगर निगम सर्वेक्षण से पहले चार माह तक तैयारी करता रहा था। मार्च में सर्वेक्षण आठ दिन तक चला, लेकिन सर्वेक्षण के डेढ़ माह बीतने के बावजूद अभी तक परिणाम नहीं आए है। इस बार इंदौर के अलावा सूरत और नवी मुंबई भी नंबर वन रैंकिंग की दौड़ में है। पिछले साल इंदौर के साथ सूरत शहर को संयुक्त पुरस्कार मिला था।

इस बार इंदौर को प्रीमियर लीग में शामिल किया गया है। इसमें सूरत और नवी मुंबई भी है। तीनों शहरों में स्वच्छता के आंकलन का पैमाना अलग रहा। पिछले साल तीनो शहर टॉप थ्री में थे, हालांकि इस बार सर्वेक्षण के समय भी इंदौर की स्वच्छता कमजोर रही। सर्वेक्षण के समय शहर की गंदी बेकलेन के कारण इंदौर को नंबर कम मिल सकते है। इस बार शहर के नाले प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पाया।

कुछ नाले भले अस्थाई रूप से साफ कर दिये गए, लेकिन सालभर नालों में गाद, गंदगी और कचरा नजर आता है। इस मामले में इंदौर को नंबर कम मिल सकते है। इंदौर रैंकिंग में सबसे ज्यादा नंबर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में पाएगा। यह व्यवस्था इंदौर में दूसरे सभी शहरों से अच्छी है। लोग खुद अलग-अलग कचरा फेंकते है। इंदौर की स्वच्छता में सबसे बड़ी ताकत लोगों की जनभागीदारी है। लोग कचरा घरों और संस्थानों में संभालकर रखते है। उन्हें खुले में नहीं फेंकते। सुबह आने वाले कचरा वाहनों में ही उसे डाला जाता है।

इस सप्ताह आपके सितारे
21 मई 2025 से 27 मई 2025

किसी को संतान पक्ष से होगी पीड़ा तो किसी के व्यय ज्यादा होंगे

मेष- इस सप्ताह कारोबार में उछाल दिखेगा। आय भी बढ़ेगी। किसी व्यक्ति के सहयोग से कोई कार्य होने की संभावना भी है। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। व्यय ज्यादा होंगें। संतान पक्ष पीड़ित करेगा। वाहन सुख उत्तम। माता का स्वास्थ्य ठीक-ठीक रहेगा।

वृषभ- इस सप्ताह प्रेम संबंधों में सावधानी रखें अन्यथा परेशानी होगी। जीवनसाथी का शारीरिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार ठीक-ठीक रहेगा। वाहन सावधानी से चलावें। बेवजह के विवादों से बचें। भूमि संबंधी कोई सौदे न करें। कारोबार ठीक रहेगा। आवक अच्छी होगी।

मिथुन- इस सप्ताह शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। शत्रु भी परेशान कर सकते हैं। मित्र भी वांछित सहयोग नहीं देंगें। संतान संबंधी चिंता का निवारण होगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग अच्छा रहेगा। बेवजह के विवादों में न पड़ें।

कर्क- जीवनसाथी का सहयोग एवं व्यवहार इस सप्ताह मध्यम रहेगा। संतान पक्ष सहयोग करेगा। आवक मे वृद्धि होगी। कारोबार वृद्धि की तरफ बढ़ेगा। मित्रों से मिलना-जुलना बढ़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वाहन सावधानी पूर्वक चलावें। विवादों में न पड़े अन्यथा कष्ट होगा। परिजनों का उत्तम सहयोग मिलेगा।

सिंह- इस सप्ताह संतान पक्ष आपको पीड़ित कर सकता है। अनायास कोई नुकसान भी हो सकता है अतः सावधान रहें। जीवनसाथी का सहयोग एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध ठीक रहेंगें। कारोबार में हल्का सा उतार-चढ़ाव दिखाई देगा। यात्रा को टालें। भूमि-भवन के विवाद में न पड़ें।

कन्या- शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन हानि अथवा अधिक व्यय के योग है। पारिवारिक परिवेश अमूमन अच्छा रहेगा। कोई रुका कार्य होगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग मध्यम रहेगा। कारोबार भी मध्यम रहेगा।

तुला- जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं व्यवहार ठीक-ठीक रहेगा। किसी व्यक्ति के व्यवहार से मन दुखी होगा। अस्थियों में कष्ट संभव है। वाहन कष्ट दे सकता है। परिजनों का वांछित सहयोग मिलेगा। आय संतोषजनक रहेगी। बेवजह के व्यय भी हो सकते हैं। प्रेम सबंधों के प्रति सावधान रहें।

वृश्चिक- मन में कुछ खिन्नता रहेगी। मानसिक तनाव भी रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग एवं व्यवहार अच्छा रहेगा। पिता को या पिता से कष्ट संभव है। माता का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। किसी रोग का अल्प कष्ट होगा। विशेष रुप से श्वसन अथवा उद्विकारों के लिए लापरवाह न रहें। शत्रु पीड़ा होगी।

धनु- इस सप्ताह आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बेवजह के विवादों से बचें। भूमि संबंधी कार्य कष्ट दे सकते हैं। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा। कोई प्रतिक्षित कार्य होगा। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह धनात्मक है।

मकर- इस सप्ताह माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी पर आंख मींच कर भरोसा न करें। संतान पक्ष कुछ परेशान कर सकता है, किन्तु जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा। कारोबार अच्छा चलेगा। आवक अच्छी होगी। कोई रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा।

कुंभ- यात्रा के योग बन सकते हैं किन्तु उसे टालें। नौकरी अथवा प्यार में कुछ ऋणात्मकता दिखाई देगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की तरफसे पर्याप्त सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध फले-फूलेंगे। आवक मध्यम।

मीन- कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह श्रेष्ठ है। किसी रुके हुए कार्य के होने से खुशी होगी। जीवनसाथी का व्यवहार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। संतान पक्ष आंशिक रूप से पीड़ित कर सकता है। बेवजह के विवादों में न पड़ें। वाहन सुख उत्तम। कारोबार मध्यम रहेगा। लाभ सीमित होंगें। वाहन सावधानी से चलावें।

श्रीमान उमेश पांडे
ज्योतिष एवं वास्तुविद
महात्मा गांधी मार्ग, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
मो. 8602912030

इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां

■ **सूर्य** - सूर्य मेष ■ **चंद्र** -वृश्चिक से मकर ■ **मंगल** - कर्क
■ **बुध**-मीन ■ **गुरु** - वृषभ ■ **शुक्र** - मीन ■ **शनि** - मीन
■ **राहु**- मीन ■ **केतु**-कन्या

11 फ्लाईओवर ब्रिज के लिए हुए सर्वे में 8 चौराहो की रिपोर्ट आई

आधे चौराहे पास, आधे फेल

राइजिंग इन्दौर
■ विपीन नीमा

शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और शहरवासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में 11 फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए निजी कंपनी द्वारा किए गए फीजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है।

इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चार चौराहे पर फ्लाईओवर बन सकते हैं, जबकि चार चौराहे ऐसे हैं जहां ट्रेफिक का दवाब कम होने के कारण फ्लाई ओवर की आवश्यकता नहीं है। शेष तीन चौराहे का भी सर्वे पूरा हो चुका है। इस चौराहों की सर्वे रिपोर्ट पर अभी इंजीनियरों द्वारा एनालिसिस चल रहा है। इस कारण यह खुलासा नहीं हो पाया है कि इन चौराहों पर फ्लाय ओवहर ब्रिज की आवश्यकता है या नहीं। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण ने 11 चौराहे पर फ्लाईओवर ब्रिज बनवाने के लिए सर्वे करवाया था। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर चार चौराहो पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाते है तो उस पर कुल 248 करोड़ रु की लागत आएगी।

शहरों में इसलिए जरूरी है फ्लाय ओवर ब्रिज बनाना

शहरो में फ्लाईओवर और ओवरब्रिज महत्वपूर्ण हैं, खासकर ट्रैफिक और विकास को ध्यान में रखते हुए। वे ट्रैफिक जाम को कम करने, समय की बचत करने और शहरों को गति प्रदान करने में मदद करते हैं। फ्लाईओवर एक सड़क को दूसरी सड़क के ऊपर से गुजारते हैं, जिससे नीचे की सड़क पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहता है और चौराहों पर जाम की समस्या कम होती है। फ्लाईओवर शहरों में आवागमन को तेज करते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दो माह पूर्व शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर निगम, आईडीए और प्रशासनिक अफसरों ने एक बैठक में निर्णय लिया था कि शहर के भीड़भाड़ वाले 11 चौराहों पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाएं।

- 4 चौराहे पर FOB की जरूरत नहीं
- 4 चौराहे पर बन सकते FOB
- तीन चौराहे का हो रहा है एनालिसिस
- तीनों चौराहों की रिपोर्ट एक सप्ताह बाद आएगी
- टोपोग्राफीक सर्वे
- ट्रैफिक सर्वे एनालिसिस

4 फ्लाईओवर ब्रिज पर 248 करोड रुपए की लागत आएगी

- चौराहो के सर्वे ऐसे किए
- टर्निंग मूवमेंट सर्वे
- डी सर्वे (ओरिजिनल डेस्टिनेशन)

शहर के इन 11 चौराहों का हुआ फीजिबिलिटी सर्वे

जानकारी के मुताबिक शहर के जिन 11 चौराहों का फीजिबिलिटी सर्वे करवाया गया है उनमें जंजीरवाला चौराहा, घंटाघर चौराहा, पत्रकार कालोनी चौराहा, मधुमिलन चौराहा, एग्रीकल्चर कॉलेज चौराहा, छावनी चौराहा, अग्रसेन चौराहा, आजाद नगर चौराहा, टॉवर चौराहा, चाणक्यपुरी चौराहा तथा गोपुर चौराहा शामिल है। सरकार ने सर्वे करवाने की जिम्मेदारी इंदौर विकास प्राधिकरण को सौंपी थी, जिसने एक अनुभवी कंपनी को नियुक्त कर उससे इन चौराहों का सर्वे करवाया था। कंपनी ने इन चौराहों की ट्रैफिक व्यवस्था पर गहन अध्ययन किया। एक से डेढ़ माह तक चले सर्वे में चौराहों की वीडियोग्राफी - फोटोग्राफी, वाहनों की आवाजाही, ट्रैफिक का दबाव, वाहनों का मूवमेंट आदि बिंदुओं पर अध्ययन किया गया था। कंपनी ने 11 में से 8 चौराहे की रिपोर्ट आईडीए को सबमिट कर दी है, जबकि तीन चौराहे की सर्वे रिपोर्ट पर एनालिसिस किया जा रहा है।

देखिए विभिन्न चौराहों की सर्वे रिपोर्ट

इन चार चौराहों पर बनाए जा सकते है पर FOB

टॉवर चौराहा -
लंबाई - 523 मीटर
चौड़ाई - 12 मीटर
लेन - 3 लेन
लागत - 37 करोड़ रु
फायदा - 1.20 लाख वाहनों को लाभ (60 प्रतिशत क्षमता)

चाणक्यपुरी चौराहा -
लंबाई - 586 मीटर
चौड़ाई - 17 मीटर
लेन - 4 लेन
लागत - 65 करोड़ रु
फायदा - 1.30 लाख वाहनों को लाभ (55 प्रतिशत क्षमता)

गोपुर चौराहा -
लम्बाई - 648 मीटर
चौड़ाई - 12 मीटर
लेन - 3 लेन
लागत - 90 करोड़ रु
फायदा - 85 हजार वाहनों को लाभ (71 प्रतिशत

प्राधिकरण की नई योजनाओं से बनेगा नया इंदौर...

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

7 नई योजनाओं के माध्यम से होगा 1200 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास

इन योजनाओं में 45 किलोमीटर की मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण शुरु

विकास के कामों पर खर्च होंगे 3000 करोड़ रु

इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तावित 7 नई आवासीय योजनाओं के माध्यम से नए इंदौर की रचना की जाएगी। इन योजनाओं में 1200 हैकटेयर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इन योजनाओं में शामिल निजी जमीन के एवज में लैंड पूलिंग एक्ट के तहत काम किया जा रहा है। इन योजनाओं में मास्टर प्लान की 45 किलोमीटर लंबी सड़कों का भी निर्माण होगा।

पिछले वर्ष इंदौर शहर को चार फ्लावर बीच की सौगात देकर इन चौराहों पर यातायात की मुश्किलों को इंदौर विकास प्राधिकरण ने समाप्त कर दिया था। इंदौर के अब तक के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब एक ही वर्ष में शहर को चार फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात मिली। विकास की इस कड़ी को प्राधिकरण के द्वारा अपनी नई टीपीएस योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्राधिकरण की ओर से इंदौर शहर के विभिन्न हिस्सों में 7 नई टीपीएस योजनाएं घोषित की गई है। इन योजनाओं पर लैंड पूलिंग एक्ट के तहत काम भी शुरू हो गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में आवासीय एवं व्यावसायिक विकास के उद्देश्य से कुल 7 नगर विकास योजनाओं को विकसित किया जा रहा है। लगभग 1200 हेक्टेयर में विकसित की जा रही इन नगर विकास योजनाओं पर 3 हजार करोड़ से अधिक का व्यय किया जा रहा है। TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 9 एवं TPS 10 में मास्टर प्लान सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह कार्य अभी तेज गति के साथ चल रहा है। इन सभी योजनाओं में लगभग 45 किलोमीटर लंबी मास्टर प्लान सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसमे से सर्वाधिक 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण TPS 8 में किया जाना है।

इसी योजना में आगामी सिंहस्थ के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण सड़क एमआर 12 का निर्माण किया जा रहा है। एमआर 12 सड़क की लंबाई 9.5 किमी है, जो बायपास को सीधे उज्जैन रोड से जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण हो जाने से दूसरे शहरों से उज्जैन जाने के लिए आने वाले नागरिक इस सड़क के माध्यम से सीधे बाईपास से उज्जैन रोड पर पहुंच जाएंगे। इन लोगों को इंदौर शहर में आने और अपना समय तथा ईंधन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह महत्वपूर्ण सड़क बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगी। इन योजनाओं में किया जा रहे काम के बारे में पूछे जाने पर प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरवार ने बताया कि सभी योजनाओं में अभी पहले चरण में प्राथमिकता के साथ मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इन सड़कों के निर्माण से शहर के नागरिकों को सुविधा उपलब्ध हो सके की। इन सड़कों का कार्य पूरा होने के बाद इन योजनाओं की 24 मीटर और 18 मीटर की चौड़ाई वाली सड़कों का निर्माण शुरू किया जाएगा। इन सभी योजनाओं के माध्यम से सर्व सुविधायुक्त नए इंदौर की रचना करने की कोशिश की जा रही है। इन योजनाओं में प्राधिकरण के द्वारा 56 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जा रहा है। इस ग्रीन बेल्ट में पहली बार किड्स प्ले जोन भी बनाया जाएगा।

इतिहास के पन्नों से...

यह तस्वीर 1918 की है जब इंदौर के राजवाड़ा पर शाही कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

7 महीने में की 25 शादियां

भोपाल में फर्जी शादियों के जरिए लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की मानटाउन थाना पुलिस ने की है। आरोपी अनुराधा पासवान अब तक करीब 25 व्यक्तियों से नकली शादी कर उन्हें ठग चुकी है। 23 साल की अनुराधा पासवान मूल रूप से यूपी के महाराजगंज जिले के कोल्हुई बाजार की रहने वाली है। वर्तमान में वो भोपाल में रह रही है।

शादी के 3 दिन बाद कैश-जेवर लेकर फरार हो गई

3 मई 2025 को मानटाउन निवासी विष्णु शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसे खंडवा निवासी सुनीता और पप्पू मीना ने मनपसंद लड़की से शादी करवाने का झांसा देकर भोपाल निवासी अनुराधा का फोटो दिखाया। इसके बाद सवाई माधोपुर कोर्ट में फर्जी एग्रीमेंट के जरिए 2 लाख रुपए लेकर शादी करा दी। शादी के महज तीन दिन बाद ही अनुराधा घर से कैश, जेवर और मोबाइल लेकर फरार हो गई।

आरोपी फर्जी शादी कर कालापीपल में रह रही थी

मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने भोपाल में स्थानीय मुखबिरों की मदद से फर्जी शादी गिरोह से संपर्क किया। टीम के एक सिपाही को अविवाहित बताकर फर्जी शादी कराने की योजना की मदद से फर्जी शादी गिरोह से संपर्क किया। टीम के एक सिपाही को अविवाहित

बताकर फर्जी शादी कराने की योजना बनाई गई।

इसी दौरान एजेंट द्वारा दिखाई गई तस्वीरों में फरार अनुराधा की पहचान हुई। टीम ने भोपाल के कालापीपल स्थित पन्नाखेड़ी गांव में दबिश देकर अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया। अनुराधा हाल ही में एक और फर्जी शादी कर वहीं रह रही थी।

2 से 5 लाख रुपए तक वसूल कर शादी करवाते थे

पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह गिरोह भोपाल से ऑपरेट होता था। इसमें रोशनी, सुनीता, रघुवीर, गोलू, मजबूत सिंह यादव, अर्जन नाम के सदस्य शामिल हैं। ये लोग भोपाल के अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं। मोबाइल पर शादी के इच्छुक लोगों से संपर्क कर महिलाओं के फर्जी फोटो दिखाते थे और 2 से 5 लाख रुपए तक वसूल कर शादी करवा देते थे। शादी के 3-4 दिन बाद ही दुल्हन बनी युवती घर का सारा माल समेटकर से भाग जाती है।

फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। ठगे गए अन्य पीड़ितों से भी संपर्क किया जा रहा है। पुलिस चोरी किए गए जेवर और नगदी की बरामदगी की कोशिश भी कर रही है।

डिफरेंट न्यूज

ग्वालियर नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति अवैध

ग्वालियर नगर निगम के आयुक्त संघप्रिय गौतम की नगर निगम में आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैध माना है। कोर्ट ने धारा-54 का उल्लेख करते हुए उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। साथ ही नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ 61 कर्मचारियों को भी 15 दिन में अपने मूल विभाग में भेजने के आदेश दिए हैं। दरअसल, नगर निगम आयुक्त के पद के लिए सरकार को आदेश में धारा 54 के तहत डेपुटेशन पर भेजने का आदेश जारी करना था, लेकिन यह नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने इसी को आधार बनाया है।

खंडवा के कब्रिस्तान में महिलाओं की कब्र से छेड़छाड़

खंडवा के कब्रिस्तान में किसी अज्ञात व्यक्ति ने महिलाओं की कब्र को खोदकर पैरों वाले हिस्से से कफन को खुला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सीएसपी और कोतवाली टीआई मौके पर पहुंचे। लोगों ने आशंका जताई है कि तांत्रिक क्रिया के चलते ऐसा किया गया है। बड़ा कब्रिस्तान में महिलाओं के अलग-अलग शव शुक्रवार के दिन ही दफनाए गए थे। परिजनों ने बताया कि सभी कब्र करीब 50 साल उम्र की महिलाओं की है। सभी कब्रों को पैरों की तरफ से फर्श हटाकर खोल गया, साथ ही शव पर डले कफन के साथ भी छेड़छाड़ की गई हैं।

अहमदाबाद में होगा आईपीएल का फाइनल

आईपीएल 2025 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी मैदान पर क्वालिफायर-2 भी खेला जाएगा। यह फैसला मंगलवार को BCCI की एक बैठक में लिया गया। बोर्ड ने बताया कि क्वालिफायर-1 और एलिमिनेटर मैच मोहाली के पास मुल्लानपुर स्टेडियम में खेला जाएगा। इतना ही नहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 23 मई को बेंगलुरु में होने वाले मैच को बारिश के कारण लखनऊ शिफ्ट कर दिया है। भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण 9 मई को IPL को रोका गया था। फिर 17 मई से लीग के शेष मैचों की शुरुआत हुई। अब तक मौजूदा सीजन के 61 मैच खेले जा चुके हैं। अभी 13 मैच बचे हुए हैं।

प्रकाशक एवं मुद्रक गौरव गुप्ता द्वारा स्वामी अशर्फीलाल विमलादेवी मीडिया सर्विसेस प्रा.लि. के लिए डी. बी. कॉर्प लि., 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ, इंडस्ट्रियल एरिया, सांवेर रोड इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 401-402, डी.एम. टॉवर जंजीरवाला चौराहा, इंदौर 452001 से प्रकाशित। संपादक- दीपक गुप्ता, कार्यकारी संपादक-जितेंद्र जाखेटिया*। फोन नंबर-0731-4032200, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2013/52898* समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार।